

यनिक पदार्थ (उर्वरको को छोड़कर), शोध, शेषजों, कपड़ों (रगेंछापे या अन्य किसी प्रक्रिया से तैयार किये हुये) सम्मिलित है। कागजों के उत्पाद, कागज तथा लुग्दी चीनी परिशोधित खाद्य पदार्थ, बनस्पति तेल तथा बनस्पति घी, रबड का सामान काच और सीमेन्ट व जिप्सम के उत्पादों का उद्योग आदि से है। जिसमें 363 आवेदन 31-10-73 से पहले प्राप्त हुये तथा 43 आवेदन 1-11-73 को सुप्रवाही पद्धति के लागू होने के उपरान्त प्राप्त हुये। पुराने आवेदनों में से 284

आवेदनों को निपटाया जा चुका है तथा शेष 79 आवेदनों को प्रशासकीय मंत्रालयों के परामर्श से शीघ्र निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। 1-11-73 के बाद मिले 43 आवेदनों में से 7 आवेदनों पर कार्यवाही की जा चुकी है तथा आशा की जाती है कि शेष 36 आवेदनों को निर्धारित समय के अन्दर निपटा दिया जाएगा। 1-3-74 की अनिर्णीत आवेदनों का वर्षवार तथा प्रकार वर व्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष प्रकार	नये उपक्रम	नयी जिन्से	पर्याप्त विस्तार	काम चलाते रहने का लाइसेस	योग
1970 .	3	.	..	3	6
1971 .	6	1	1	1	9
1972 .	15	4	3		22
1973 .	34	7	5	6	52
1974 .	15	2	3	6	26

(फरवरी तक)

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DISTRIBUTION OF A PRIVATE FACTUAL REPORT ON DEEPENING CRISIS IN INDIAN ECONOMY BY THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE WORLD BANK

श्री मधु लिमये (बाका) अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की श्रौर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में वक्तव्य दें

“भारत सहायता सब के 13 राष्ट्रों में वितरण हेतु, तैयार की गई भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए सकट पर एक प्राइवेट सतथ्य रिपोर्ट विश्व बैंक के अध्यक्ष के कार्यालय

द्वारा समाचारपत्रों का वितरित किए जाने का समाचार।”

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN): Mr. Speaker, Sir, the various reports appearing in newspapers regarding a factual report prepared for members of the Aid India Consortium have come to the notice of the Government

We have checked with the World Bank and we have been assured that there is no substance in the report that the office of the President of the World Bank had distributed the report in question to newspapers. What seems to have happened is an unauthorised leakage, the origin of which is under investigation by the World Bank.

(Shri. Yeshwantrao Chavan)

The paper was prepared in response to a request by the Consortium countries three years ago that World Bank should prepare a study on India's debt situation and aid requirements on a long term basis. This paper is prepared by the World Bank and distributed to members of the Consortium in connection with a meeting of the Working Party of the India Consortium scheduled to take place in Paris in April, 1974 to discuss the level and pattern of Consortium support to India's development during the next and succeeding years. The specific purpose of the paper is to help members of the Consortium, appreciate the development effort which we propose to mount during the Fifth Five Year Plan and to provide such resources as they have been providing or can provide in future in freely usable forms to the maximum extent possible.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि भारत के कई अखबारों में यह खबर छपी है कि यह जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है यह स्वयं बैंक के अफसरों ने कई समाचार-पत्रों के बीच वितरित की। और यह भी कहा गया है कि सबसे पहले एक भारतीय अखबार और "न्यू यार्क टाइम्स" को यह दी गई और उस के बाद दूसरे लोगों के हाथ में यह पडी। "टाइम्स आफ इंडिया" ने यहाँ तक कहा है कि जब यह लोग इस को वितरित करना चाहते थे तो उन के ऊपर दबाव डाला गया कि कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव तक इस को प्रसारित नहीं किया जाय। यह मेरी बात नहीं है। मैं टाइम्स आफ इंडिया से पढ़ रहा हूँ।

"They were evidently dissuaded from releasing the report during the U.P. elections lest it should damage the Congress Party's chances and Mrs. Gandhi's standing."

मंत्री महोदय इसकी भी सफाई दें कि क्या हमारे दूतावास ने इस तरह का कोई प्रयास किया था कि चुनाव के पहले प्रकाशित न हो। जब इस में से कई हिस्से प्रकाशित हो चुके हैं तो क्या आप कम से कम अब सदन को विश्वास में लेंगे और जो मूल रपट है जो आपके पास जरूर पहुँची होगी, इस की एक कापी सदन की मेज पर रखेंगे ताकि पता चल सके कि वास्तव में इस में क्या है। जहाँ तक तथ्यों का सवाल है, उसके बारे में मेरी मंत्री जी से यह मांग है।

जहाँ तक विश्व बैंक का सवाल है इस रपट में दो तथ्यों का पता चलता है। एक यह कि विश्व बैंक के द्वारा जिन अर्थविकसित और दूसरे देशों को कर्जा दिया गया उन देशों में सब में अधिक कर्जा अकेले भारत को दिया गया है। 1973 की विश्व बैंक की यह रपट है और इस में कहा गया है कि 370 करोड़ का कर्जा दिया गया है अकेले भारत को। इस रपट में यह भी कहा गया है कि अर्थविकसित देशों में जो सब से गरीब तीस करोड़ लोग है पूरी अर्थविकसित दुनिया में उन में से अकेले भारत में तेरह करोड़ सबसे गरीब लोग रहते हैं। इस हालत में इस रिपोर्ट का अपना महत्व है। इस रिपोर्ट में दो बातें विशेष जोर दे कर कही गई हैं। एक यह कि पाचवी योजना की अवधि में इस देश को लगभग एक करोड़ टन गल्ला मगवाना पड़ेगा पाच वर्षों में और जो हमारा योजना आयास है उसका अनुमान साफ है इससे मेल नहीं खाता है। दूसरी बात यह है कि पाचवी योजना के लिए विदेशी सहायता का जो अनुमान किया गया है। यानी 500 करोड़ डालर उसके बारे में वर्ल्ड बैंक वालों का कहना है कि 1210 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, एक गल्ले के आयात के लिए और दूसरे तेल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसको ले कर तेल के आयात को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए भी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। वैसे सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है कि विदेशी

महायत्ता के बारे में जो सही स्थिति है उससे सरकार जनता को अवगत नहीं कर रही है। बजट के बारे में भी कई लोगों ने यह आलोचना की है कि आपने विदेशी सहायता के जो आकड़े हैं उस में रूस के द्वारा गेहूँ के रूप में आपको मदद की गई है या ईरान के द्वारा जो कर्जा दिया गया है इमको आपने दिखाया तक नहीं है। क्या यही सिलसिला विदेशी सहायता के बारे में चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विश्व बैंक के द्वारा गल्ले के आयात के बारे में जो अनुमान किया गया है उसके बारे में इस वक्त सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इममें हमें अवगत कराया जाए। क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं है? दूसरे विदेशी सहायता के बारे में तेल के दामों में जो वृद्धि हो गई है और गल्ले का जा सकट है उसको ले कर क्या यह बात सही है कि 1210 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त किए बिना आपकी योजनाएँ ठीक ढंग में नहीं चल पाएंगी?

बीच में ईरान के बादशाह ने यह बयान दिया था कि तेल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसके चलते उनके पास जो राशि आने वाली है उसका क्या किया जाए यह उनके सामने भी मवाल है। एक सुझाव उन्होंने यह दिया था कि पेट्रोलियम पैदा करने वाले देश, विकसित देश और अ विकसित देश तीनों को मिला कर एक कोई संगठन बनाया जाए और उम संगठन की मार्फत अ विकसित देशों के विकास में मदद की जाए। क्या इस तरह का सुझाव भी आपके पास आया है। जो विश्व बैंक की रपट है उससे भी कुछ इस तरह का इशारा मिलता है कि जो तेल पैदा करने वाले देश हैं उनके ऊपर अ विकसित देशों को निर्भर रहना पड़ेगा और उसके लिए बें तैयार हो जाएंगे। ये जो तेल पैदा करने वाले देश हैं खास कर साउदी अरब, कुवैत, ईरान, ईराक आदि, क्या इनके साथ इमके बारे में कोई बातचीत हुई है? यदि इस तरह का संगठन बनेगा तो क्या वह विश्व बैंक से अलग रहेगा या विश्व बैंक से सहयोग से काम करेगा? इसका भी खुलासा

आप करे और भारत सरकार को जा प्रतिक्रिया है उमके बारे में भा बनाने की आप कृपा करे।

MR. SPEAKER Mr. B. V. Naik, I am not allowing you. But a word of what you say will go on record.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: The hon Member has again made of reference to official leakage by the World Bank I think I have explained the position in my statement

श्री मधु लिमये दिस इज कार्ट दी रैट आफिगल्ले। आरिगल रिकेज नहीं दिया गया है। दोनों में फर्क है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण आरिगल रिकेज नहीं है लेकिन रिकेज ह इम में कार्ट शक नहीं है। किमने किया ह इमक वार म इनक्वायरा व कर रहे है। मर लिग कार्ट राय देना मुशिकल है इमके बारे में।

As far as the report is concerned, it is a confidential report of the World Bank and I cannot afford to agree to lay it on the Table of the House

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: (Gwalior): Have you got a copy of the report?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: Of course.

I have explained what is the purpose of this report. The purpose of this report is to help the Consortium countries, with whom we will be discussing the question of aid, relief of debt, etc, some time in the month of April in Paris It is, really speaking, some sort of aid-memoire given by the World Bank to these countries to find out the balance of payments position, the economic development of India and its requirement in the Fifth Five Year

[Shri Yeshwantrao Chavan]
Plan. This is, really speaking, the purpose of the report. This is all that I can say at the present moment.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Why do you try to hide it?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: It is not a question of my hiding it. It is a question of World Bank hiding it. It is their confidential report. I cannot lay it on the Table of the House.

SHRI PILOO MODY (Godhra). What about the report in the *Times of India* regarding persuading them not to release it, before U P. elections?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN Nobody has persuaded anybody to publish it or not to publish it before the U.P. elections because this report has nothing to do with the U.P. elections.

श्री मधु लिमये : किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया इन्होंने। अखबारों से मैंने उद्धरण दिए हैं। वो सवाल मैंने उठाए हैं, एक गल्ले आयात के बारे में। हिन्दू तथा दूसरे अखबारों में यह आया है और कोटेशन में है। दूसरे विदेशी सहायता के अनुमान के बारे में मैंने नवाल उठाया है। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि क्या वास्तव में विश्व बैंक का यह अनुमान गल्ले के आयात के बारे में और विदेशी सहायता के बारे में सही है और उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इस में छिपाने की क्या बात है। अखबारों में आ चुका है आपको अपनी प्रतिक्रिया बतानी चाहिए।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I seek guidance from you.

My main point is one of procedure If the hon. House wants to discuss the question of foreign exchange requirement projections made in the

Fifth Five Year Plan, certainly, the House is entitled to know about it, and it can separately discuss that matter. But, if you are discussing this question in connection with the contents of this report, I have my limitations and I cannot discuss the contents of this report.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय अपनी तरफ से कम से कम यह तो बता सकते हैं कि इस वक्त—जब ड्राफ्ट प्लान बना, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ—विदेशी सहायता और गल्ले के आयात के बारे में उन का अनुमान क्या है।

MR. SPEAKER: I think the Minister is perfectly right.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN It is very difficult to make any long term projections with any precision as things may be changing and so these exercises are naturally made from time to time I cannot say

श्री मधु लिमये : इस वक्त क्या स्थिति है? अध्यक्ष महोदय, क्या आप इतना भी जवाब नहीं दिलायेंगे?

MR. SPEAKER He has taken up the position that so far as this report is concerned he cannot give out anything concerning that or that he is not in a position to do so But, if you want to have information on the subject, there is a separate occasion for that.

श्री मधु लिमये : यह इसी में आता है। क्या आप इतना भी जवाब नहीं दिलायेंगे? मैं ने कहा है "इर्रेस्पेक्टिव आफ दि वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट"। यह इसी में आयेगा। अगर इन प्रश्नों का जवाब नहीं आना है तो इस कार्लिंग एटेंशन को एडमिट करने का क्या मतलब है?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप जाने और मिनिस्टर साहब जानें।

श्री मधु लिमये : जब अग्रूरी रिपोर्ट आ चुकी है तो मंत्री महोदय को पूरी रिपोर्ट के बारे में बताने में क्या आपत्ति है ? जब वर्ल्ड बैंक ने स्वयं इस को लाक किया है तो सरकार को इस में क्या आपत्ति है अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को यह जानकारी देने के लिये आदेश दें ।

SHRI PILOO MODY: There is a point here.

There is something which appeared in the newspapers. This is not confidential to anybody. It is public property. It is the newspaper report that Shri Madhu Limaye wishes to discuss. The report goes on to make certain allegations. The Minister cannot merely say that the Finance Ministry is totally ignorant of what has been published in the papers regarding a report which it considers so important that it should be kept confidential. Therefore, what has appeared in the newspapers should at least be discussed without any inhibition.

MR. SPEAKER: The Minister takes up the position that it is a confidential document even if it has partly been reported, and he will not put himself in that position. Is it correct?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: Yes, Sir.

SHRI PILOO MODY: Tomorrow he may say that the *Times of India* is a confidential document.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग बहुत ही सीधी सी है । मैं कह रहा हूँ कि विश्व बैंक की रिपोर्ट को छोड़ दें । मंत्री महोदय कहते हैं कि स्थिति बदलती रहती है बार-बार मूल्यांकन करना पड़ता है । आज 13 मार्च है । 13 मार्च का मंत्री महोदय का क्या मूल्यांकन है, इस का तो पता चले । इस में विश्व बैंक का क्या सम्बन्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विश्व बैंक के बारे में बता दिया है । उन का कहना है कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो इस के बारे में अलाहिदा बहस कर लें ।

श्री मधु लिमये : बहस तो हम बजट पर इसकथान के दौरान करेंगे ; इस वक़्त तो मैं सिर्फ़ जानकारी चाहता हूँ । मेरा प्रश्न यह है कि एज ग्रान 13 मार्च गल्ले के आयात और विदेशी सहायता के बारे में मंत्री महोदय का इवैल्युएशन क्या है ।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: How does it arise out of this question?

MR. SPEAKER: That is what I am telling.

I can allow a separate question. The hon. Member may bring it and I will send it to the Minister.

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा अन्याय हो रहा है । आशिर यह कार्लिंग एटेंशन नॉटिस काहे के लिए है ? मंत्री महोदय वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को रखने के लिए तैयार नहीं है । हम उस को छोड़ देते हैं । हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय गल्ले के आयात और विदेशी सहायता के बारे में सरकार के वर्तमान मूल्यांकन की जानकारी दें । वह दो वाक्यों में यह जानकारी दे सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं ।

MR. SPEAKER: He is agreeable, if you ask separately.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I want a ruling from you. The hon. Minister said something which is of great importance. Here is a document which has received much publicity, which concerns the Government of India. That document he is reluctant to lay on the Table of the House, Sir, I am sorry to repeat myself. Here is a document which has received publicity in the world

[Shri Jyotirmoy Bosu]

press and in the national press and the document involves the Government of India. What is it that is standing in the way for him to lay it on the Table of the House? I cannot understand this. This is contempt of the House, Sir..

MR. SPEAKER: You are an expert on this, in bringing out the documents, you can use that instrument in the case of the World Bank also.

श्री मधु लिमबे : अध्यक्ष महोदय, मैंने ईरान के शाह के बारे में पूछा है। क्या मंत्री महोदय उस का भी जवाब नहीं देंगे? क्या उस का भी वर्ल्ड बैंक से सम्बन्ध है? तो फिर आप इस कॉलिंग एटेंशन नोटिस को डिस-एलाउ कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उस के लिए आप अलाहिदा कॉलिंग एटेंशन नोटिस दीजिए।

श्री मधु लिमबे : यह इसी के तहत आता है।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: Sir, that question will have to be addressed to the Petro Chemicals Ministry.

श्री मधु लिमबे : मैं विदेशी सहायता और विकास के बारे में कह रहा हूँ। बातचीत यह करते हैं। विदेशी मुद्रा का मामला इन के तहत आता है। अध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह चलेगा, तो मुझे समा त्याग करना पड़ेगा। आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं। मंत्री महोदय को ईरान के शाह के बारे में जवाब देना पड़ेगा। आप उन से जवाब दिलवाईये। वह एक भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, we are faced with a very pecu-

liar situation. The hon'ble Minister says he has received an advance report of the World Bank on aid requirements of India and he has also admitted that it is a confidential document. Some of these news items have appeared in the papers, especially, in the *Times of India*. I am in a peculiar position, Sir. You have admitted the Calling Attention Motion. Questions can be asked. For each and every question if he says, this is of a confidential nature, I cannot just discuss it. I just want to know how is it that these news items percolated in the newspapers? They tried to ascertain about it from the World Bank Authorities and these World Bank authorities say that it is not an authorised version and they are trying to find out how leakage was done. So, it is a very difficult thing for me to ask a question in these circumstances. But let me put a question, and let me try if I can extract something from the inscrutable Finance Minister. My first question is this. Does the Government of India consider the World Bank report as being helpful to India or unhelpful to India?

SHRI PILOO MODY: It has to do with truth, not with help.

SHRI SAMAR GUHA: If it is a helpful report, whether any advance publicity, either due to leakage or by manipulation on the press highlighting certain aspects of the important issues involved regarding economic development of India, had done any harm to this country or not? In the *Times of India Report*,—not in the Indian express report,—they tried to attribute some motives to the office of the President of the World Bank. In view of all these things, I think, it is necessary for the hon Minister to clear up those points. Mr Mc Nemara after he became the President of the World Bank has proved very helpful to the underdeveloped countries. After he became President,

he doubled the quantum of I.D.A. assistance to the poor countries. To India, 40 per cent of the I.D.A. assistance has been given.

In 1973, the quantum of I.D.A. assistance amounted to Rs. 430 crores. In the last two decades, India had never received such a huge quantum of foreign aid.

MR. SPEAKER I am inviting your attention to the main motion and not to Mr McNamara and other things.

SHRI SAMAR GUHA: The entire question relates to him.

SHRI PILOO MODY: You might be aware that Mr. McNamara is the President of the World Bank and it is his report we are discussing.

SHRI SAMAR GUHA: It is also reported in the press that the House of Representatives tried to curtail the U.S. quantum of aid to I.D.A. Mr. McNamara by going out of the accepted track took unusual measures. He vehemently criticised that.

In view of that, I consider that our Government should make the position clear. We should not rub the sentiment of the World Bank in the wrong end. From the World Bank only we can expect a certain helpful attitude and also a certain help for our foreign exchange through the assistance of Consortium.

In view of this fact, I want to know from the Government whether the reports that have appeared in the Press are the correct versions of the portions of the World Bank Report submitted to the Government of India where it has highlighted a serious economic crisis, particularly, on the food front which may develop in India.

Secondly, it is also stated that the rupee trade between India and the Communist country is not helpful to India. The words used are—it is the negative aid transfer. It is also

stated that the estimate made is about five billion dollars of foreign exchange. If India gets this much of foreign exchange during the Fifth Plan period, it will be too inadequate. The estimate of the World Bank is 12.1 billion dollars of foreign exchange which would be required by India. When this estimate was made by the World Bank, at that time, the crude price did not jump up abnormally so high. In view of this fact also, I want to know from the Government whether it is a fact or not that the Government has received the World Bank Report and whether the newspapers version of the report claiming as the World Bank Report is correct. If not, what is the correct version of the Report? Has the Government received the report from the World Bank? If not, the reasons therefor.

During the Fifth Plan period, the assistance from the World Bank for India will be of the order of ten billion dollars on food import to avoid a serious crisis. Would the Government tell us whether the rupee trade between India and the Communist country is against the interest of India and would it tantamount to negative aid transfer from the Communist countries? If so, the reasons therefor.

Also I want to know whether the Government agrees with the assessment of the World Bank that five billion dollar foreign aid during the Fifth Plan period is too inadequate and, in reality, India will require more than 12.1 billion dollars. If not, the reasons thereof.

Lastly, I want to know whether the leakage of some of the facts of the Report have created any adverse effect on the aid-giving consortium countries.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: The hon. Member has asked me some general questions. Possibly, they

[Shri Yeshwantrao Chavan]

relate to the Calling Attention Notice. On is whether the World Bank Report is helpful or not. We are examining and studying the report and I cannot explain the view about the Report. Whether it is helpful or not will be judged by the effect that we ultimately have in the discussions at Paris. I cannot say whether it will be helpful or not. As far as the attitude of Mr. McNamara is concerned it has been useful and sympathetic to the developing countries including India.

Sir, the other questions relate again to the contents of the Report and I am sorry in the light of what we have decided just now I do not think I can express any view.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, I had raised the point whether those reports represent the correct version of the Report incorporated in the Annual Report of the World Bank?

MR SPEAKER: He wants to know so far as the report which has appeared in the Press whether it is a correct part of that Report or not.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: It is very difficult for me to give any opinion on that because he wants opinion. (Interruptions)

SHRI SAMAR GUHA: Sir, the Government has admitted that they have received the Report of the World Bank. The Report of the World Bank is in the possession of the Government. In the background of that certain reports appeared in the Press. Government have admitted that it is leakage of the Report. If it is so, it is my pertinent question whether those reports which appeared in the Press are a correct version of the portion of the Report of the World Bank or not?

श्री मधु सिमये : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा अभी हम लोगों ने तय

किया है तो आप ने कुछ तय किया है कि इस को कांफिडेंशियल रखा जाय या टेबल पर न रखा जाय ? आप ने कुछ कहा है ? हम जानना चाहते हैं इनका जा निणय है क्या आप उस से सहमत हैं, उसके सहभागी या हिस्सेदार है या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे ता अपनी ही यहा मुश्किल बहुत है, यह वर्ल्ड बैंक का और आ पडा है .

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We want your ruling, Sir.

MR SPEAKER: Here is the ruling given by my predecessor on 26th February, 1965

"The Government cannot be compelled to admit or deny the correctness of any alleged copy of document classified secret or confidential. It is necessary for the Member who quotes from the document to certify that he has verified from his personal knowledge that the document is true."

It is for you to verify

श्री मधु सिमये : मैं आप के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

अध्यक्ष महोदय : जो कांफिडेंशियल डॉक्यूमेंट है उस में मिनिस्टर को कैसे कहेंगे कि बताओ ?

श्री मधु सिमये : आप न अभी जो निर्णय पडा उस में कहा गया है कि सरकारी दस्तावेज को रखने के लिए कम्प्लेन नहीं कर सकते।

लेकिन वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट थोडे ही है। अध्यक्ष महोदय, यह रूलिंग इस पर कैसे सप्लाई होती है ? आप के निर्णय को हम एक दम मानते हैं शिरोधार्य करते हैं

अध्यक्ष महोदय : आप का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट ने कान्फ़ीडेंशियल रखना है, उस के लिये सरकार को मजबूर किया जाए ?

The World Bank's report is confidential for the Government. Government want to keep that as confidential.

SHRI MADHU LIMAYE: This is not the Government decision.

SHRI PILOO MODY: Tomorrow, a secret CIA report may come to the hands of the Government. Is it bound to keep it a secret?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order. I have made a submission already that on what the hon. Finance Minister has stated, we are waiting to hear from you your ruling or your observation or whatever it be. Now, you have read out an old ruling given by your predecessor, Sardar Hukam Singh. I can also quote it from memory.....

MR. SPEAKER: It is not an old ruling.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Kindly tell us how that ruling is relevant in this case. Here, Shri Madhu Limaye or Shri Samar Guha is not laying anything on the Table of the House. So, they are not required to authenticate it. They are only talking about the press report that has come out which the Finance Minister has stated to be correct.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: No; I have not said that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He said that it had leaked out. It is on record. Let the tape be examined. He said that the information had leaked out, and it is on record. It has received full coverage in the international press and the national press. So, how is it that this House could be kept in darkness, when the

whole world is talking about it? Are we living in the harem of this Government?....

SHRI SAMAR GUHA: That ruling is not applicable in this case.

SHRI MADHU LIMAYE: The case in which that ruling was given has to be distinguished from the present case. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Let hon. Members please set down. Let them not come to a clash for nothing....

SHRI SAMAR GUHA: My point of order is this. You have quoted a ruling. In my opinion that does not apply to the present case.

Firstly, the document in question is not a document of the Government of India. So far as the rules are concerned, the specifically refer to documents which concern the Government of India only. Secondly, my submission to you is this. What are we discussing today? What is the nature of the calling attention? The nature of the calling-attention is the leakage of certain news. Unless we know the veracity of the news and what the news is, how can we discuss about the leakage? How can we discuss what effect it will have? You have already admitted the calling attention on the basis of the document itself. Therefore, it is very important and very pertinent....

MR. SPEAKER: I am not at all prepared to go beyond the ruling that has already been given.

SHRI SAMAR GUHA: How could it be classified as secret? You can ask the Government.

MR. SPEAKER: Let the hon. Member sit down. Let him not exert too much over this. He has already taken a lot of time.

SHRI SAMAR GUHA: Government are bound to come out with a statement" whether it is correct or not.

MR. SPEAKER: The ruling....

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): May I have half a minute?

MR. SPEAKER: So the practice in future should be that when a member gets up, the Speaker should sit down!

SHRI N. K. P. SALVE: I am requesting you.

MR. SPEAKER: You are a lawyer yourself. How do you know what I am going to say? God help this House! What is this going wrong with these people?

This matter was raised in the House of Commons in the U.K. on 25th February, 1945. When a member quoted from a secret protocol, the Foreign Secretary, Mr. Eden, made the following observation. Some protocol was involved in which other powers may have been concerned and they were asked to give their ruling. This was one of the bases on which a ruling was given by Shri Hukam Singh.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order, arising out of what you have said. This is neither a protocol nor is there another sovereign power involved in it....

अध्यक्ष महोदय : कोई रीजनेबिल बात भी का जाय तो पता नहीं क्या हो जाता है बेकार की बहस खड़ी करते हैं।

SHRI SAMAR GUHA: May I make a submission? The discussion on this call attention can be suspended. I request you to give thought over the matter and give a considered ruling afterwards.

MR. SPEAKER: I have already very well thought over the matter. I am very clear about it, clear like anything.

SHRI SAMAR GUHA: On a point of order again. How is the issue of protocol relevant here.

MR. SPEAKER: No, no.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I want to make a submission.

MR. SPEAKER: No.

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...

MR. SPEAKER: No. Nobody has my permission to speak. I am not allowing you.

Please sit down. I am very clear about it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order.

MR. SPEAKER: No point of order.

आम लोगों की आवाज पड़ गई है रोज कुछ न कुछ करने की। हर बात पर कुछ करते हैं। आप को पुराने स्पीकर की कॉलिंग पढ़ कर नायी है फिर भी वही हाल है कि बहस बढ़ाते जायें।

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय, मुझे इस निर्णय से सतोष नहीं है, और मैं इस के विरोध में सदन त्याग कर रहा हूँ।

(Shri Madhu Limaye then left the House.)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is not relevant at all.

MR. SPEAKER: I am so sorry. Do not question the ruling of the Speaker.

DR. KAILAS (Bombay South): Whether it is relevant or not is to be decided by you, Sir, and once you have decided that it is relevant, no further question arises.

SHRI SAMAR GUHA: On a point of order. Just now you mentioned about the origin of that ruling. In

your statement, you have said that this ruling relates to a protocol between two states....

MR. SPEAKER: No, no. That was quoted in the ruling. Then the ruling was given. I have quoted the ruling.

SHRI SAMAR GUHA: It relates to determining the relations between two sovereign states. Here the relation between the world Bank and the Government of India is not a protocol of that type or any relation between two sovereign states. Therefore, that ruling does not apply in this case.

MR. SPEAKER: Please sit down. The report of the World Bank is confidential and the Minister has to keep that report confidential and he cannot be compelled to give that information. On this the rule is very clear.

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur): That is very correct.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order arising out of what you have said. There are two things. I have pointed out that the earlier ruling of Sardar Hukam Singh does not apply.

MR. SPEAKER: There are a number of others, not one.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: They are not producing any document here which they claim to be genuine and which they did not authenticate. That can be ruled out. The second thing is, as the Professor has said, that there is no protocol involved here. The world press has got hold of it. Why should we be prevented from having a look at it? You should make a suitable observation on this. Otherwise, this House will become supine.

MR. SPEAKER: Shri Savant.

13.00 hrs.

Order please. Shri Shankerrao Savant.

SHRI SHANKERRAO SAVANT (Kolaba): Sir, from the hon. Minister's reply, it appears that the report, whatever be its content, was made with good intention of giving India the much-needed help during the Fifth Plan period. What is really objectionable is the method of its unauthorised publication. The food requirements of India may have been correctly stated or may have been exaggerated in the report. Everybody is entitled to hold his own opinion about it. But it seems—

MR. SPEAKER: What is your question?

SHRI SHANKERRAO SAVANT: I am coming to it. Only two years back, India stopped the import of foodgrains and it has more or less reached self-sufficiency.

MR. SPEAKER: Mr. Savant, have you brought it ready-made from home?

SHRI SHANKERRAO SAVANT: I am giving the points... (Interjections).

MR. SPEAKER: You may ask a question. These are matters over which I have given my ruling.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, I submit it is very unfair. Before putting the questions certain introductory comments are allowed to every Member.

MR. SPEAKER: I have already over ruled such observations. You may ask a direct question about it.

SHRI SHANKERRAO SAVANT: Whether it is correct or incorrect, the intention is good, because the report is meant to give aid to India during the Fifth Plan period. Even suppos-

(Shri Shankerrao Savant.)

ing there are incorrect statements. The Finance Minister is right in saying that the contents of the report cannot be discussed, because ultimately it is on the basis of this report that we will have to fight in Paris to get aid for India. (Interruptions).

MR. SPEAKER: Trying to excel each other.

SHRI SHANKERRAO SAVANT. The press has given lurid publicity I am quoting from the *Times of India* which says that the World Bank is annoyed with India for its lack of earnestness in meeting the crisis both in regard to food and oil. Of course, this type of heading ought not to have been there, and it is that which naturally exercises our mind. It is thus clear that the report is meant to be used for political purposes and not for siding India in her present economic difficulties

Will the Finance Minister put in a strong protest about this kind of use of the report to the World Bank and to the persons who leaked the report to the press?

MR. SPEAKER: I can deal even with Shri Madhu Limaye but not this gentlemen!

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I am supposed to make a reply about what? Ultimately we will be required to put our case in Paris.

MR. SPEAKER: You must be more considerate to your own Members.

SHRI BHOGENDRA JHA: Without beating about the bush, I proceed from the fact, that the report has leaked out is correct. The written statement of the Finance Minister

makes it abundantly clear that what has leaked out is the correct position of the report which is confidential. So, on this point no question need be asked. That is abundantly clear from his reply. (Interruptions).

MR. SPEAKER: As a question

SHRI SAMAR GUHA: The Calling Attention motion has become a joke.

MR. SPEAKER: The rule is such that when you quote that, you will have to give a guarantee, you will have to give it in writing. Now, you are asking the other side to give it

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar): The dangerous aspect of this leakage is that in the background of the US decision to establish its war-base in the Indian Ocean and in the background of—(Interruptions)

AN HON. MEMBER: The word** should not be allowed to go on record.

MR. SPEAKER: This remark will be expunged. Prof. Samar Guha has no business to interrupt the Member. I did not call him. Nothing will go on record. All such remarks will not go on record

SHRI BHOGENDRA JHA: In the background of the declaration of the U. S. Ambassador to rename the Indian Ocean as some other sea and the sending of the US atomic warship to the Indian Ocean, and the leakage of this report at this particular juncture when we are seeing food riots in several parts of the country, I want to know whether the Government of India have themselves submitted anything of this sort or approached the World Bank, because the World Bank is dominated by the Government of the United States? Are they making some sort of

approacher or leakages of this sort to make us give up our declared objective of self-reliance, because the leakage gives a blow to our objective of self-reliance and it is trying to help the forces inside the country and also outside, those who are against India becoming self-reliant. In this background I want to know whether the decision that we will have to import two million tonnes a year, and ten million tonnes in the next five years, and that 121 billion dollars and not 5 billion dollars in terms of foreign exchange would be required, has been there. Is the Government considering some such thing, and has it given some such hint to the Government of the United States that it is going to change its policy of self-reliance? Is it a fact or not?

Secondly, the World Bank had leaked out the report, particularly when the Government is hesitant in enforcing wholesale take-over of the wheat trade.

Again, there are rumours that the Government is going to surrender to forces inside and outside the country who want *laissez faire* in the country, so that the starving people will have no other option but to come out in the streets. In such a background, I would like to know whether the leaked-out report is going to act as a pressure on the Government of India to give up the policy of feeding our people on the basis of controlled prices, to hold the price line of essential commodities particularly foodgrains. I would like to know the Finance Minister's view as to whether it is going to act as a pressure on the Government of India.

Thirdly, as it has been made out, the report did not come out during the UP elections. Naturally, if it had come out at that time, people would have become more curious about it and this would have encouraged the forces inside and outside the country who are in favour of such estimates

and such assessment of the Indian situation or who are in favour of such policies. But it has been leaked out at a time when we are having troubles in Gujarat and other parts of the country. I would like to know whether the Government of India is going to protest to the World Bank, and tell them that suitable action should be taken from whichever quarter the report has leaked out and that the action taken in this regard should be made known to the Government of India. These are the three questions, on which, I would like to have the Finance Minister's reply.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN

As far as the last part is concerned, whether this leakage is being used as a pressure on the Government of India to influence its policies, I can assure this hon. House that such leakages or any other leakages whatever may be the motivation, will not be allowed to influence the policies of the Government. Planning is to be undertaken with the approval of Parliament and we will certainly stand by the principles of self-reliance. I can assure the hon. House that there is no question of ourselves getting alarmed. As far as the question of protest is concerned they are themselves making investigations about it. We have made certain enquiries. If there has been leakage from the official side certainly, we would have lodged a protest. But, at the present moment when investigations are going on, it will be premature to say whether we are going to protest or not.

SHRI BHOGENDRAS JHA They have made an estimate that India will require 2 million tonnes of foodgrains a year, over the next 5 years and that the country's foreign exchange requirements would be of the order of 121 billion dollars during the next 5 years. I would like to know whether the Government of India agrees with that estimate.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN
 Whatever projections we have made in our Plan document, if at all they have to be revised, they will be revised by us in the Planning Commission. Therefore, when we have not done the exercise, how can I give any opinion about it? But, I can say that our basic policy remains the same.

SHRI BHOGENDRA JHA But, they have made out a report

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN
 What can I do?

SHRI R S PANDEY (Rajnandgaon) When I saw the news item in the *Times of India* yesterday I was very much agitated. I am not very much concerned about the leakage. The hon. Finance Minister has correctly replied that investigations are going on and that he will be informed. Sir, it is not a question of leakage. If, as a result of the leakage, a glorious picture had come out about the situation in India, we would not have been exercised very much about it. The important and very pertinent question is, the contents of the report, which deals with the food position, the fertiliser position, foreign exchange position, Five Year Plans etc. that this country has become bankrupt, it has not been able to become self-reliant and that we are a helpless people. Individuals like me are agitated over the contents of this report. Since the report is confidential—it may be true or may not be true,—it is very difficult for me to put any question. Sir, when you are going to participate in the meeting in Paris some time in April, you should convey the feelings of the House that this kind of uncharitable remarks, which damage the personality of our sovereign country will not be tolerated and that people of India are very much agitated over it. If it is confidential, I can put the question confidentially and I would like to have the answer also confidentially.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN.
 I have no answer to give.

MR SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, I have given notice of an adjournment motion. Out of 188 MLAs in the Gujarat Assembly, 84 have already resigned. What is stopping the Government from dissolving the Legislature? Apart from giving the adjournment motion, I have also written to the Speaker. Sir, I would like to have your observation. Why is the Government sticking to the same position?

MR SPEAKER: You had a discussion on this subject.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The Home Minister was expected to make a statement covering this.

MR SPEAKER: This matter was raised in the debate.

1317 hrs

RE ALLEGED PREVENTION OF VISITORS FROM MEETING MEMBERS OF PARLIAMENT—contd

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर)
 अध्यक्ष महोदय, मैंने आप को दो बातों के बारे में लिखा है। एक तो कल जो रिसेप्शन आफिस में हुआ, उसकी ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया है . . .

अध्यक्ष महोदय। एसी बातों को बहाने की क्या जरूरत है आप मुझे लिख दिया करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मैंने आपको लिखा है। मुझे जानकारी मिली है कि थापिके सेक्रेटरियट में बताया है कि मुझ से कोई लडका मिलने के लिए नहीं आया। वह गलत बात है। मैं खुद वहाँ गया था—उस समय भी थायलैंड के